भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2769

उत्तर देने की तारीख - 05.08.2026

नेवा पर विधानमंडलों का शामिल किया जाना

2769. श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री रमेश अवस्थीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
डॉ. के. सुधाकरः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री अरुण गोविलः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल शासन के लिए "वन नेशन, वन एप्लीकेशन" जनादेश को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लीकेशन (नेवा) पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों को शामिल किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे विधानमंडलों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने "डिजिटल हाउस" के संचालन को पूरी तरह से अपना लिया है तथा इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए संवितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता की विशिष्ट राशि कितनी है;

(ग) नेवा में रीयल-टाइम बहुभाषी अनुवाद, स्वचालित प्रतिलेखन और अनुक्रमित अभिलेखागार सहित एआई-संचालित कार्यप्रणालियों को शामिल करने की स्थिति क्या है; और

(घ) संवेदनशील विधायी जानकारी की सुरक्षा तथा देश भर में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा और नेटवर्क लचीलेपन को बढ़ाने हेतु कार्यान्वित ठोस प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 37 विधानमंडलों में से 33 विधानमंडल 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' (नेवा) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से, 21 विधायी सदनों को नेवा परियोजना के अंतर्गत डिजिटल विधानमंडलों में परिवर्तित किया जा चुका है।

(ख) नेवा परियोजना के अंतर्गत डिजिटल सदनों में परिवर्तित होने वाले 21 विधायी सदन हैं: पंजाब विधानसभा, ओडिशा विधानसभा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, नागालैंड विधानसभा, मणिपुर विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, सिक्किम विधानसभा, त्रिपुरा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, मेघालय विधानसभा, मिजोरम विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, गुजरात विधानसभा, पुडुचेरी विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, असम विधानसभा, राजस्थान विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए इन विधायी सदनों को केंद्र सरकार द्वारा ₹138.17 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

(ग) नेवा पब्लिक पोर्टल भाषिणी द्वारा विकसित ए.आई.-संचालित बहुभाषी अनुवाद टूल्स से लैस हैं, जो कंटेंट का भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेज़ी में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(घ) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) सॉफ्टवेयर सूट में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को विधायी कार्य संचालन हेतु एक मज़बूत, सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण मिल सके। कार्यान्वित किए गए मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:

I. नेवा सॉफ़्टवेयर को सुरक्षित एनआईसी मेघराज 2.0 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है।
II. एक समर्पित डिज़ास्टर रिकवरी साइट किसी भी विपरीत घटना की स्थिति में डेटा की विश्वसनीय रिकवरी सुनिश्चित करती है।
III. सॉफ़्टवेयर की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं।
IV. लॉगिन के लिए टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस को केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित करता है और संवेदनशील विधायी कार्यप्रवाह के दुरुपयोग को रोकता है।

*****